



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032025-261946
CG-DL-E-25032025-261946

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1359]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 2025/चैत्र 4, 1947

No. 1359]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2025/CHAITRA 4, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2025

का.आ. 1377(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अरावीथिदु वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1857(अ), तारीख 08 जून, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसे पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकेगी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1857(अ), तारीख 08 जून, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1857(अ), तारीख 06 जून, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के लिए, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“5. निगरानी समिति. – केन्द्रीय सरकार एक निगरानी समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

- | | | |
|--------|--|---------------------|
| (i) | क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर क्षेत्र, मैसूर | - अध्यक्ष, पदेन; |
| (ii) | हंसुर विधानसभा क्षेत्र से विधान सभा सदस्य* | - सदस्य, पदेन; |
| (iii) | कर्नाटक सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि | - सदस्य, पदेन; |
| (iv) | कर्नाटक सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधि | - सदस्य, पदेन; |
| (v) | क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर | - सदस्य, पदेन; |
| (vi) | उपायुक्त, मैसूर जिला | - सदस्य, पदेन; |
| (vii) | प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ जिसे प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए | - सदस्य; |
| (viii) | पर्यावरण या वन्यजीव या विरासत संरक्षण सहित प्राकृतिक संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जिसे प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए | - सदस्य; |
| (ix) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, मैसूर | - सदस्य, पदेन; |
| (x) | उप वन संरक्षक, वन्यजीव प्रभाग, मैसूर | - सदस्य सचिव, पदेन। |

*(अन्य बातों के साथ-साथ कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा, यदि आवश्यक हो कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष से अनुमति सहित सुसंगत अनुमोदन प्राप्त करने के अध्यक्षीन)।

6. निगरानी समिति के कार्य. - (1) विनिर्दिष्ट निगरानी समिति, वास्तविक स्थल परिस्थितियों के आधार पर, उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची के अंतर्गत आती हैं और उसके पैराग्राफ 4 के अधीन दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को भेजे गये हैं।

- (2) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और इसके पैरा 4 की सारणी में प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, की संवीक्षा निगरानी समिति द्वारा स्थल विनिर्दिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।
- (3) निगरानी समिति के सदस्य सचिव या उप आयुक्त या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करने के लिए सक्षम होंगे।
- (4) निगरानी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता करने के लिए विभाग से प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों के प्रतिनिधि या पणधारियों को आमंत्रित कर सकेगी।
- (5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-V में विनिर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।
- (6) केंद्रीय सरकार अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे।”

[फा. सं. 25/135/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक “जी”

टिप्पणी.- मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 08 जून, 2017 को विस्तृत का.आ. 1857 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2025

S.O. 1377(E).—WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section (3) section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Arabithittu Wildlife Sanctuary, Karnataka in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1857(E), dated the 08th June, 2017;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1857(E), dated the 08th June, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 1857(E), dated the 08th June, 2017 namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

“5. **Monitoring Committee.** — The Central Government hereby constitute a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely: -

(i)	Regional Commissioner, Mysore Region, Mysore	Chairman, <i>ex officio</i> ;
(ii)	Member of Legislative Assembly from Legislative Assembly constituency of Hunsuru*	Member, <i>ex officio</i> ;
(iii)	Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka	Member, <i>ex officio</i> ;
(iv)	Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka	Member, <i>ex officio</i> ;
(v)	Regional Officer, Mysuru, Karnataka State Pollution Control Board	Member, <i>ex officio</i> ;
(vi)	Deputy Commissioner, Mysore District	Member, <i>ex officio</i> ;
(vii)	One expert in ecology from reputed institution or university to be nominated by the Government of Karnataka after every three years	Member;
(viii)	One representative of a non-governmental organisation working in the field of environment or wildlife or natural conservation including heritage conservation to be nominated by the Government of Karnataka after every three years	Member;
(ix)	Chief Executive Officer, Zilla Panchayat, Mysore	Member, <i>ex officio</i> ;
(x)	Deputy Conservator of Forests, Wildlife Division, Mysore	Member Secretary, <i>ex officio</i> .

*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals inter alia including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required).

6. **Functions of Monitoring Committee.** — (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.
- (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in proforma specified in Annexure V.
- (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”.

[F. No. 25/135/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist “G”

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 1857(E), dated the 8th June, 2017.